श्री माधवराव सिंधिया: मैं अपनी वह टिप्पणी वापस लेता हूँ *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय विदेश मंत्री को अपने कहे के लिए क्षमा मांगनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे कार्यवाही-वृत्तांत देखने दें और यह पता करने दें कि यह शब्द उसमें है या नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें देखना होगा कि कार्यवाही-वृत्तांत में क्या है। कृपया इस बात को समझें।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): महोदय, उन्होंने 'गाली' शब्द का प्रयोग किया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब तक मैं कार्यवाही-वृत्तांत को नहीं देख लूं। मैं इस बारे में कुछ कैसे कह सकता हूँ?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मणिशंकर अय्यर, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर: इससे साबित होता है कि अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की शालीनता उनमें नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में अब कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरनगर की हालत पर पहले बहस होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को रिप्लाई के बाद, जीरो आवर में उठा सकते हैं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या लगभग तीस थी। जो सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे, वे भी चर्चा में रुचि रखते थे और जहां थे, वहीं से चर्चा को देखने का प्रयास कर रहे थे, सुनने का प्रयास कर रहे थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, चर्चा का आरम्भ श्री माधव राव सिंधिया ने किया। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): यह गलत है। एक अखबार ने छाप दिया, आप उसी को पढ़ते हैं। सारे अखबार पढ़ते तो पता चल जाता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मेरा मतलब है कि कांग्रेस की ओर से चर्चा शुरू की। वैसे मुलायम सिंह जी ने चर्चा का आरम्भ किया था और कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं, लेकिन मैं माधवराव जी के भाषण से शुरू करना चाहता हूं, इसलिए कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोले। उनका पहला पैरा, पहला परिच्छेद मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> "आगरा शिखर वार्ता ने पूरे देश को भ्रम में डाल दिया। यह और भी तकलीफदेह है कि यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री, सरकार तथा माननीय विदेश मंत्री भी भ्रम में दिखे। वे इस दुविधा को दूर नहीं कर पाए कि यह शिखर वार्ता सफल रही या असफल रही।"

[हिन्दी]

उनके अनुसार सभी असमंजस में हैं, सारा देश भ्रम में है और वे स्वयं भ्रम में हैं, इसका भी उन्होंने परिचय दिया। उस वार्ता के संबंध में मतभेद हो सकते हैं। जिस उद्देश्य से वार्ता आयोजित की गई थी, वह कहां तक प्राप्त हुआ, लेकिन यह कहना कि सारा देश असमंजस में है, सरकार भ्रम में है, यह ठीक नहीं है। यह देश के साथ और सदन के साथ न्याय करना नहीं है। जिन परिस्थितियों में वार्ता हुई, उनसे सभी परिचित हैं।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

यह प्रश्न उठाया गया है कि आपने तैयारी नहीं की थी। इससे पहले लाहौर में एक वार्ता हुई थी, वह वार्ता हमारे दोनों देशों के संबंध में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उस वार्ता के बाद कारगिल में क्या हुआ, यह एक अलग परिच्छेद है। हम दोनों को जोड़ें, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब लाहौर घोषणा की बात सारी दुनिया कहती है, हम भी उसका उल्लेख करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों की जो कड़ी है, उसमें लाहौर वार्ता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उस वार्ता के बाद में जो अंतिम घोषणा की गई थी, उसमें आतंकवाद की निन्दा की गई थी। किसी भी प्रकार का आतंकवाद, किसी भी रूप में चलने वाला आतंकवाद, यह आलोचना का विषय था, पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया था। यद्यपि उस समय भी छुटपुट घटनाएं हो रही थीं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसने सारी तस्वीर बदल दी है। हम पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को इस बात के लिए तैयार नहीं कर सके कि अक्रास दि बोर्डर टैरेरिज्म का उल्लेख होना चाहिए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर उसे स्वतंत्रता की लड़ाई की संज्ञा दे दी। यह हमारे लिए सर्वथा अप्रत्याशित था और उसी समय से वार्ता का वातावरण बिगड़ा।

बार-बार उनसे कहा गया है कि आतंकवाद से समस्याएं हल नहीं होंगी। आतंकवाद दोहरा हथियार है। पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो आतंकवाद से प्रेरित हैं। जो वहां की सरकार के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही हैं। यहां तक कि जनरल मुशर्रफ को कहना पड़ा कि अगर मेरा बस चले तो इस तरह के आतंकवाद को मैं गोली से मार दूं। आतंकवाद उनके लिए भी समस्या बन रहा है। इसलिए आतंकवाद को किसी रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। आतंकवाद न तो आजादी की लड़ाई है और न उसे जेहाद कहा जा सकता है, लेकिन कठिनाई यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है। कभी मित्रता का वातावरण बनता है, कभी युद्ध होता है, कभी युद्ध विराम होता है। यह सिलसिला पिछले 50 साल से चल रहा है। लेकिन हमारी नीति रही है कि हम पड़ौसियों के साथ अपने संबंध सुधारें, कमजोरी से नहीं।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पाकिस्तान के जो पत्रकार आये थे, उनमें से कुछ यह कहते सुने गए कि कश्मीर की घाटी हमारी झोली में पके हुए फल की तरह से गिरने वाली है। हिन्दुस्तान की फौज थक गई है। हिन्दुस्ता परेशान हो गया है और इसलिए अब कश्मीर में हिन्दुस्तान अपने हितों की रक्षा के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करेगा। किस प्रकार यह भ्रम पैदा हुआ, किस तरह से ये खबरें फैलीं। प्रतिनिधिमंडल आते-जाते रहते हैं। कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं भी सक्रिय हैं। लेकिन इस तरह के प्रचार ने हो सकता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी प्रभावित किया हो। अब किसी के मन में गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए, भारत सशक्त है, उसकी सेनाएं किसी भी आक्रमण का और किसी भी आंतरिक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गलत समझा है। अगर इसके आधार पर उन्होंने अपनी नीति बनाई, रणनीति बनाई, तो इसमें विफल होना बिल्कुल निश्चित था। हम कभी आतंकवाद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर को तो हम अटूट अंग कहते हैं। मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा कि आपके लिए जम्मू कश्मीर जमीन का टुकड़ा हो सकता है। जम्मू तो वे मुश्किल से कहते थे, लद्दाख छोड़ देते थे, कश्मीर पर ध्यान केन्द्रित कर रहे थे और कहते थे कि कश्मीर का जब तक हल नहीं होगा, तब तक हमारे संबंध सुधरेंगे नहीं। कश्मीर पर भारत हमेशा से बातचीत करने के लिए तैयार रहा है।

'शिमला समझौते' में भी हमने माना था कि जम्मू-कश्मीर के ऊपर आगे बातचीत होगी। हम बातचीत के लिए तैयार हैं और शिखर सम्मेलन में भी कश्मीर के साथ जम्मू-कश्मीर के सवाल को लेकर काफी बातचीत हुई मगर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को हमने कहा कि अगर आप जम्मू-कश्मीर पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं तो फिर जम्मू-कश्मीर के सारे इतिहास को देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपने आक्रमण किया था, किस तरह से जम्मू-कश्मीर की जनता को अपनी इच्छा के अनुसार भारत से मिलने से रोका था, किस तरह से कबाइलियों ने हमला किया। पाकिस्तान जब जम्मू-कश्मीर की बात करता है तो हथियारों की सोचता है और मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ। मैं सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अगर उस समय कबाईली हमला नहीं करते तो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास आज है, वह भी न होता। वार्ता का आधार कहां था? इस बात को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते और इसलिए मैंने उनसे बार-बार कहा कि आइए और उन विषयों को लेकर संबंध सुधारें।

हमने उन्हें एजेंडा दिया। दो बार हमने एजेंडा दिया, कांफीडेंस बिल्डिंग मैजर्स का ऐलान किया जो एकतरफा था। हमने कहा कि हम इसे लागू करने के लिए तैयार हैं लेकिन आप केवल कश्मीर की रट मत लगाइए। कश्मीर पर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का मामला उलझा हुआ है। आपके लिए कश्मीर जमीन का टुकड़ा हो सकता है, हमारे लिए कश्मीर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। किस तरह से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यह आजादी की लड़ाई नहीं है, यह आतंकवाद का नग्न प्रदर्शन है और इसके चलते, स्थिति में परिवर्तन होना मुश्किल है। मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान अपने रवैये पर पुनर्विचार करेगा। मुझे विश्वास है कि वह अपना दृष्टिकोण बदलेगा। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। मेरे लिए पड़ौसी देशों के साथ मित्रता

एक संकल्प का विषय है। 1977 में जब मैं विदेश मंत्री बना था तब भी मैंने प्रयास किया था कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, लोगों के आने-जाने में आसानी हो, वीजा और पासपोर्ट के नियम सरल किये जायें लेकिन बाद में हिंसा का रास्ता पकड़ा गया। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भी इस बात को अनुभव किया है और उन्होंने लिखा है: आयाज अमीर 'डॉन' से संबंधित हैं। उनके लेख का एक अंश मैं उद्धृत करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

> ''यह पूर्ण सत्य है कि जेहाद एक शब्द जिसका यहां बहुत हल्के तौर पर उपयोग किया जा रहा है का कश्मीर में कोई भविष्य नहीं है। वहां पर बहाए गए खून और की गयी कुर्बानियों को देखते हुए यह कहना कटु कथन है पर दुर्भाग्य से यह सही है। विद्रोह को जारी रखने से भारत में रक्त बह सकता है जैसाकि इसने पहले भी दशकों से इस काम को विश्वसनीय परिणामों के साथ किया है। भारत की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है और घाटी को अव्यवस्थित कर रखा है। पर यह राज्य की स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख सकता। इतना पिछले 53 वर्षों के इतिहास से स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो पकिस्तानी सेना पूर्ण युद्ध से प्राप्त नहीं कर सकी, उसे जेहादी मारो और भागो की रणनीति से प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते।''

[हिन्दी]

यह पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है। पाकिस्तान, काश्मीर को प्रारम्भ से ही शस्त्रों से लेने का प्रयास करता रहा है। अब उसने देखा कि सेना के बल पर कश्मीर को पाना संभव नहीं है, तो उसने प्रौक्सी-वार का तरीका अपनाया है। आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। देश के भीतर उपद्रव हों, इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये तरीके पाकिस्तान के रास्ते को सफल नहीं बनाएंगे। हम शांति का लगातार प्रयास करते रहेंगे। एक प्रक्रिया शुरू हुई है। अगर लाहौर के बाद सत्ता परिवर्तन न होता, तो जो कुछ वहां समझौता हुआ था, उसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में हमारे संबंध बढ़ते और काश्मीर पर बातचीत जारी रहती। मुझे कश्मीर के एक बड़े नेता ने कहा था—53 सालों में जो मामला तय नहीं हुआ, वह इतनी जल्दी तय नहीं होगा। बड़ी सच्चाई से उन्होंने कहा—हम काश्मीर की मांग छोड़ेंगे नहीं और हम जानते हैं, आप काश्मीर छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अच्छा यह है कि कश्मीर पर हम बातचीत करते रहें, मगर संबंध बढ़ायें, संबंध सुधारें, अगर लड़ना है तो गरीबी से, बीमारी से, बेकारी से। दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है और हम ऐसे संघर्ष में फंसे हैं, जिसका निकट भविष्य में निपटारा दिखाई नहीं देता है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने रास्ता बदला। मुझे याद है श्रीमती गांधी ने कहा था, जब बैठक समाप्त हो रही थी, आप शिमला और लाहौर को ध्यान में रखिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को शिमला पसन्द नहीं आया था। शिमला का नाम भी शायद उनके मुंह में गलत स्वाद पैदा करता था। उन्होंने शिमला और लाहौर को छोड़कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। जब संयुक्त घोषणा-पत्र तैयार हो रहा था, उनका प्रयास था, इसमें शिमला न आए, इसमें लाहौर का भी उल्लेख न हो। हमने इसे स्वीकार नहीं किया। भारत लगातार पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करता रहा है। पाकिस्तान से लड़ाई हुई है। लड़ाई में पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने दिल्ली में कहा था, युद्ध से यह मामला हल नहीं हो सकता है। बातचीत से हल होगा, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने यह नहीं कहा कि हमने कश्मीर में उपद्रव करने का, काश्मीर को हथियाने का एक नये युद्ध का तरीका निकाला है और उस युद्ध के तरीके से भारत एक बार बात हमारी मान लेगा।

जो बातें वन-टू-वन में हुई, उन सब पर प्रकाश डालना नहीं चाहता हूं। वे बातें एक दूसरे को विश्वास में लेकर हुई थी। लेकिन मैंने देखा कि काश्मीर के अलावा और किसी मामले में उनकी रुचि नहीं थी।

हमने कांफीडेंस बिल्डिंग्स मेजर्स ऐलान किया था, आप अगर उसे देखेंगे तो वह भारत और पाकिस्तान के संबंधों को समावेश करने वाला एक दस्तावेज है। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। चर्चा में यह आवाज उठी थी कि जब पाकिस्तान एजेंडे पर बात करने के लिए तैयार नहीं था तो आपने बातचीत तोड़ क्यों नहीं दी। इस तरह बातचीत न शुरू की जाती है, न तोड़ी जाती है। बातचीत तोड़ कैसे सकते थे और जब सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी किसी की यह राय नहीं थी कि वे एजेंडे पर सहमत नहीं हो रहे हैं। आप आगरा वार्ता को स्थगित कर दीजिए लेकिन बातचीत का भविष्य खतरे में पड़ गया, फिर भी कुछ मुद्दों पर सहमति हुई है और हम उसे आगे बढ़ाएंगे। बातचीत का सिलसिला चलेगा लेकिन बातचीत दृढ़ता के आधार पर होगी, देश की अखंडता को सुरक्षित रखते हुए होगी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वार्ता के पहले सर्वदलीय बैठक में सरकार को जो समर्थन मिला, उसके लिए मैं सभी सदस्यों और दलों का आभारी हूं। सम्मेलन की समाप्ति के बाद भी जो बैठक हुई थी उसमें भी स्वर रचनात्मक था, लेकिन अब उस स्वर में थोड़ा सा अंतर आया है, शायद यह राजनीति का पुट है। शायद चुनाव निकट आ रहे हैं, उसका परिणाम है, लेकिन मैं आलोचना का स्वागत करता हूं।

महोदय, कश्मीर का सवाल ऐसा है जिस पर हम सबको मिल कर एक राय बनानी है और दुनिया को यह बताना है कि हमारे मतभेद लोकतांत्रिक हैं। यह मतभेद राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की अस्मिता को लेकर नहीं हैं। मणिशंकर जी ने कहा कि वह

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सरकार की सहायता करने के लिए तैयार हैं। आपको शिखर सम्मेलनों का अनुभव नहीं हैं, उन्हें अनुभव है। मैं उनके अनुभव को कम करके नहीं आंकना चाहता, लेकिन उनकी पार्टी उनके अनुभव का ज्यादा लाभ नहीं उठा रही है। जब कभी हम कांग्रेस पार्टी को वार्ता के लिए निमंत्रण देते हैं और सोचते हैं कि मणिशंकर जी से कुछ मुलाकात होगी, दो-दो चोचें लड़ेंगी तो वह वहां नदारद होते हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल उन्हें अपने में शामिल नहीं करता। इसके पीछे भी कोई कंफ्यूजन हो सकता है। मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम भविष्य में उनकी और सेवाएं लेना चाहेंगे। वह अनुभवी हैं। जब वह कराची में काम करते थे तब से मैं उन्हें जानता हूं। उन्होंने कहा कि हां, यह मांग हुई थी कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू की जाए। शिखर वार्ता शुरू की जाए यह मांग हुई थी, आप शिखर पर चढ़ जाएं, यह मांग नहीं हुई थी। बातचीत तो हो रही थी और बातचीत टूटी, कारगिल के बाद टूटी। सत्ता परिवर्तन हुआ, आफिसरों के स्तर पर मिलना पर्याप्त नहीं था। यह जरूरी था कि जिसके हाथ में पाकिस्तान में सत्ता आ गई है उनका सोचने का तरीका क्या है। वह सचमुच में क्या चाहते हैं। हम मित्रता की बात कर रहे हैं। मित्रता की बात का हमें कितना जवाब मिलेगा, सही जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। एजेंडा बनाया जाए, उसे लागू किया जाए। इस पर हम लगातार जोर देते रहे। वह एक प्वाइंट का एजेंडा लेकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हे समझाया कि कश्मीर का मामला इतना सरल नहीं है। वह आगरा से शुरू करना चाहते थे, हमने कहा कि ताशकंद से यह मामला शुरू है।

कभी हमने वार्ता से इंकार नहीं किया। लेकिन कभी भी हमने डर कर वार्ता नहीं की और कभी हमने प्रचार के लिए वार्ता नहीं की। हम जम्मू-कश्मीर के बारे में बात करने के लिए अभी भी तैयार हैं लेकिन आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा, क्रॉस बोर्डर टैरेरिज्म से हाथ धोने पड़ेंगे। अब फिर आतंकवाद अपना विराट और वीभत्स रूप प्रकट कर रहा है। डोडा में जो कुछ हुआ, क्या यह आजादी की लड़ाई है? मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा की है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान अगर चाहे तो इन घटनाओं को रोक सकता है और उसे रोकना चाहिए। यह एक कसौटी है। हम मित्रता चाहते हैं यह इसकी कसौटी है।

श्री मुलायम सिंह यादव: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जो वे दबाए हुए हैं उसके बारे में आपने क्या कहा?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं उसी पर आने वाला था। आप आगे क्या कहने वाले हैं, इसका मैं अंदाज लगा लेता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप कवि के साथ ज्योतिषी भी हैं, बहुत अच्छी बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा कि अगर आप कश्मीर का मामला उठाएंगे तो हमें उसके पूरे इतिहास में जाना पड़ेगा। एक-तिहाई कश्मीर जबरदस्ती आपके कब्जे में है। आपने एक हिस्सा चीन को दे दिया और जो हिस्सा आपके पास है उसमें लोकतंत्र नहीं है। आप लोगों की राय जानने की बात करते हैं लेकिन पाकिस्तान में लोगों की राय कहां जानी गयी, जब आपने सत्ता संभाली। इस तरह की खुली बातों की वे आशा नहीं करते थे। यह अच्छा था कि ये बातें मित्रता के वातावरण में हुई। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कूटनीति में सब कुछ संभव हो सकता है और जो असंभव दिखाई देता है उसको भी हम संभव करके दिखाएंगे। बिना अपने हितों की बलि चढ़ाए हम पाकिस्तान से अपने संबंध सुधारने का प्रयास जारी रखेंगे। इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त है। लोग चाहते थे कि हम बातचीत करें। खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहते थे कि हम बातचीत के लिए जहां कहें और जिस समय कहें आने के लिए तैयार हैं। देश के भीतर भी आवाजें उठ रही थीं कि बात तो करो। आप उनकी बात मत मानो लेकिन बात तो करो, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। छोटे देशों में यह प्रचार किया गया कि भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है इसलिए वह अड़ा हुआ है कि हम बात नहीं करेंगे। हमने जब बात न करने का फैसला किया तो उस समय सही फैसला था। कारगिल के तत्काल बाद बातचीत का कोई वातावरण नहीं था। कारगिल में पाकिस्तान परास्त हुआ। *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): क्या अभी वातावरण है?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं। मैंने उन्हें यह भी बताया कि ताशकंद समझौते से कश्मीर का उल्लेख किया जा रहा है। आपने बात क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि यही तो मेरी शिकायत है। जो नेता थे वे कश्मीर पर जोर नहीं देते थे। अब मैं आया हूं तो मैं जोर दूंगा। मैंने कहा कि जोर दोगे तो बातचीत की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। कश्मीर का मामला इतना आसान नहीं है। यह हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम दो राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। पाकिस्तान उसी के आधार पर बना है लेकिन पाकिस्तान बन गया तो हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान अब भारत को आगे तोड़ने का प्रयास न करे। हम इस प्रयास को सफल भी होने नहीं देंगे। कश्मीर के बारे में कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने फैसला किया। पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं हुए।

जो गुलाम कश्मीर है, उसकी जनता की आवाज नहीं है। अभी वहां चुनाव हुए थे लेकिन बाद में वहां की सत्ता एक सेनापति को सौंप दी गई। चीन को एक हिस्सा दे दिया। किस

अधिकार से दिया? कहा गया, नहीं, अगर हमारा आपका समझौता हो गया तो चीन से हम वह हिस्सा वापस ले लेंगे। मैंने कहा कि इस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सच्चाई को पहचानिये, यथार्थ को पहचानिये और उन्माद की बात छोड़ दीजिए। आतंक का सहारा मत लीजिए। भारत बड़ा देश है और वह उदार नीतियां अपनाता आ रहा है और आगे भी अपनायेगा। लेकिन उदारता का मतलब यह नहीं कि हम अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा नहीं करें। हम यह रक्षा करेंगे और रक्षा करते हुए हम संबंध सुधारने का रास्ता निकालेंगे। इस काम में हमें सारे सदन का समर्थन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, प्रचार को लेकर बातें हुई हैं कि ठीक तरह से प्रचार नहीं हुआ। जिस तरह का प्रचार विरोधी कर रहे थे, मेरा मतलब पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से है, उस तरह के प्रचार की तरीका हम लोग नहीं अपना सकते थे लेकिन अब लगता है कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया के कारण कूटनीति में भी थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। शिखर सम्मेलन की एक मर्यादा है, उसमें काम करने का एक ढंग होता है जिसमें कदम-कदम पर वक्तव्य नहीं दिये जाते। समाचार-पत्रों को बात लीक कर दी जाये, ऐसा नहीं होता। हम पाकिस्तान के साथ सम्मेलन में गये थे। लाहौर में भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन यहां ऐसा लगा कि प्रचार को भी आक्रमण का हथियार बनाया जा रहा है। इसका असर हमारी जनता पर ठीक नहीं हुआ। लोगों ने समझा कि हम बोलते नहीं। मैंने जनरल मुशर्रफ की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल को वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने कहा कि हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकेंगे और आतंकवाद को दबाने की हमारी क्षमता को कोई कम न आंके। वे सुन रहे थे। वे नोट्स ले रहे थे लेकिन हमने उसी समय प्रेस को नहीं बताया। हमने कहा कि इन्हें सोचने का मौका दीजिए। मर्यादा का पालन होना चाहिए। हमने दृढ़ता दिखाई और दृढ़ता के साथ शालीनता भी दिखाई। हमने सारी वार्ता में मर्यादा का पालन किया। उसका हमें घाटा भी हुआ जसके लिए हम भविष्य में उपयुक्त कदम उठाएंगे। लेकिन इसके कारण हमारा प्रयास विफल हुआ, यह कहने का कोई अर्थ नहीं। समझ-बूझ बढ़ी है। कुछ मुद्दों पर आगे बातचीत चलेगी। कश्मीर पर हम बात करने के लिए तैयार रहेंगे लेकिन हमने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। उसके साथ-साथ पाकिस्तान को मेल बिठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान का रवैया बदलेगा।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था .....

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको बुलाऊंगा। आप बैठ जायें। श्री मदन लाल खुराना।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सी.एन.जी. बसों के कारण दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के अंदर एक क्राइसिस आ गया है।

आज हालत यह है कि दिल्ली के अंदर जितनी बसें हैं उनका 50 परसेन्ट यूटीलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो स्कूटर वाले और तिपहिये वाहन हैं, वे छः घंटे से लेकर 12 घंटे तक लाइनों में लगे रहते हैं। जो बस वाले हैं वे 12 घंटे से लेकर 36 घंटे तक लाइनों में लगे रहते हैं। इसके कारण वाहनों का पूरा यूटीलाइजेशन नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले पश्चिमी दिल्ली में एक सी.एन.जी. बस में आ लगी है जिसमें पांच लोग घायल हो गये हैं। उसके कारण एक संकट का वातावरण पैदा हो गया है। अभी भूरे लाल कमेटी बैठाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बद बैठी थी। उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें दो बातें बहुत डेन्जरस हैं। उसमें प्रथम यह है कि केवल सी.एन.जी. बसें ही यहां चल सकती हैं, उसी को प्राथमिकता दी गई है और दूसरा यह कहा गया है कि डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएं। दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें पूरी तरह से सी.एन.जी. बसों को चलाया जाता हो, बहुत कम सी.एन.जी. बसें होती हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मेरा निवेदन है कि दस तारीख को दिल्ली के स्कूटर और टैक्सी वालों ने पूरी हड़ताल का ऐलान किया है। उस दिन दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स राजघाट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हैं। मैंने मंत्री महोदय से प्रार्थना की है कि आप जो अपना एफीडेविट दे रहे हैं, वह ठीक दे रहे हैं। भारत सरकार ने इस बारे में जो एक्शन सोचा है वह ठीक सोचा है। मेरा कहना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट उसके अनुकूल फैसला करती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लॉ डिपार्टमैन्ट की राय लेकर कोई आर्डीनेन्स जारी करके ट्रांसपोर्टर्स को न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, इसी विषय पर आपने भी सूचना दी है; आप भी श्री मदन लाल खुराना के साथ शामिल हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*